

प्रेषक,

पीयूष सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-5

देहरादून:

दिनांक: 26 सितम्बर, 2011

विषय— सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में डायलिसिस यूनिट हेतु नलकूप का निर्माण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-7प/1/20/2011/20212 दिनांक 27.06.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में लोक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित डायलिसिस यूनिट के लिये जल आपूर्ति हेतु नलकूप की स्थापना के लिये गठित प्राक्कलन ₹ 18.80 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत ₹ 15.93 लाख (₹ पन्द्रह लाख तिरानबे हजार मात्र) के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये योजना निर्माण हेतु ₹ 15.93 लाख (₹ पन्द्रह लाख तिरानबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित करते हुये परियोजना प्रबन्धक ई0 एण्ड एम0 यूनिट उत्तराखण्ड पेयजल निगम हल्द्वानी को दी जायेगी।
2. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
3. कार्य करने से पूर्ण विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

.....2

7. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य कराया जाय।
8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपर्युक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
10. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाय।
12. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान सं0-12 के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 06-लोक स्वास्थ्य 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 99-राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-185 (P)/XXVII(3)/2011-12 दिनांक 22-09-2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव

संख्या-1178 (1)/XXVIII-5-2011-82/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. कोषाधिकारी, देहरादून एवं हल्द्वानी नैनीताल।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, हल्द्वानी नैनीताल।
6. परियोजना प्रबन्धक, ई0एण्ड0एम0 यूनिट, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी नैनीताल।
7. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
9. गार्ड फाईल।

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव